

(ख) यदि हाँ, तो उक्त गाड़ियों में बर्थों और बैठने का स्थानों में कितनी-कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख). 57 अप/58 डाउन बम्बई-पठानकोट एक्सप्रेस में स्थान बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। 28 अप/27 डाउन बम्बई-वाराणसी एक्सप्रेस से संबन्ध में 1-5-1972 से तीसरे दर्जे में बैठने की सीटें बढ़ा कर 240 की जा रही हैं।

पश्चिम रेलवे में खडवा-अजमेर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1397. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खडवा-अजमेर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और।

(ग) इस लाइन का निर्माण कार्य कब आरंभ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस खंड के बदलाव के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में भाग लेना

1398. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या बिधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों ने तारों तथा पत्रों के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों द्वारा चुनाव प्रचार में भाग लेने

के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायतों की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की शिकायतों की थी ;

(ग) क्या निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए संसद के कुछ सदस्यों ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने की माग की थी, और यदि हाँ, तो उन सदस्यों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

बिधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ, कुल मिलाकर 24 शिकायतें प्राप्त की गईं।

(ख) ये शिकायतें सामान्यतः निर्वाचन-अभियान में सरकारी कर्मचारियों के कथित भाग लेने, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और मतदाताओं के अभिवासा और संज्ञा आदि के सम्बन्ध में थी।

(ग) और (घ). जी हाँ। प्रेक्षकों को भेजने के लिए दो प्रार्थनाएं, एक श्री फूल चन्द वर्मा, संसद् सदस्य और दूसरी श्री एन० के० शेजवालकर, संसद् सदस्य से, निर्वाचन आयोग में प्राप्त हुई थी। श्री फूल चन्द वर्मा से प्राप्त शिकायत सामान्य थी और उसमें किसी विशेष निर्वाचन के क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश नहीं था। यह शिकायत जांच और रिपोर्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस निर्देश के साथ भेज दी गई कि सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्वाचन निष्पक्ष और अबाध रूप से हों। 17-गिर्द विधान सभा क्षेत्र में प्रेक्षण भेजने के लिए श्री एन० के० शेजवालकर से प्राप्त

दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि यह शिकायत निर्वाचन आयोग में मतदान के दिन अर्थात् 11 मार्च, 1972 को ही प्राप्त हुई थी।

12 Hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DISCONTENTMENT AMONG HAND-LOOM AND POWERLOOM WEAVERS IN UTTAR PRADESH ON ACCOUNT OF HIGH YARN PRICE

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur): Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Trade to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

The reported discontentment among handloom and powerloom weavers in Uttar Pradesh on account of high yarn price, non-availability of financial assistance from nationalised banks and non-disposal of accumulated stock.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): Mr. Speaker, Sir, As a result of the short crop of indigenous cotton amounting to 53 lakh bales only in 1970-71, there was an acute shortage of cotton and abnormal rise in its prices. Consequently, the prices of cotton yarn increased during this period. The annual production of both cloth and yarn in 1970-71 were the lowest in 20 years. As handloom, powerloom and hosiery units found it difficult to obtain supplies of cotton yarn at reasonable prices, a Yarn Pool Scheme was introduced in February, 1971, to alleviate to some extent the shortage of yarn felt by these sectors. The prices at which participating mills were required to sell yarn were the average of the prices of particular counts attained during October, November and December, 1970. The responsibility for distribution of the yarn allocated under the Scheme rested with the State Governments. The scheme has been extended recently to cover the quarter March-May, 1972. Allocations for this quarter will be finalised shortly.

The Textile Commissioner has allotted 1433 bales of hank yarn (for handlooms) and 4650 cases of cone yarn (for powerlooms) to U. P. for the period from October, 1971, to February, 1972, under the Yarn Pool Scheme. This allocation is equivalent to 90% of the State Government's demand for hank yarn and 86% of the demand for cone yarn. The above percentages were the highest for U. P., among all States. U. P. has accordingly been given a special treatment during October-December, 1971. Allocations for March-May, 1972, are still to be made. Discussions with representatives of the Government of U. P. are being arranged, before finalising the allocation for this quarter.

Of late there has been some difficulty in the regular supply of staple fibre yarn to the weaving units and the prices in the market rose considerably. This has been mainly due to the strike, for nearly 2½ months, in the pulp factory of M/s. Gwalior Rayons who are the main suppliers of staple fibre. However, as a result of the efforts made by the Textile Commissioner, the Man-made Fibre Spinners Association, representing the mills in Northern India, have entered into an agreement with the weavers associations to supply 50% of their production at agreed prices. Under this arrangement, the Spinners Association has placed at the disposal of the U.P. State Textile Corporation 3,500 bales per month of staple fibre yarn for distribution to weavers in U.P. The U.P. State Textile Corporation has already arranged to lift the yarn allotted to them in the month of February, 1972. The Association has issued instructions to the mills regarding similar supplies during March, 1972. These supplies are in addition to those being made by the mills through the normal trade channels at market prices. The quantity of 3,500 bales has been arrived at on the basis of 50% of the supplies normally made to the weavers in U.P. by the mills. The U.P. Government have stated that their requirements are about 11,000 bales per month. The question of assessing their exact requirements and arranging additional supplies is being considered, in consultation with the State Government and the Spinners Association.

As regard sanction of institutional finance for the development of the handloom indus-